

माननीय न्यायमूर्ति ए. एल. बाहरी और वी. के. बाली के समक्ष,

मेसर्स जय भगवान ओम प्रकाश-याचिकाकर्ता।

बनाम

निरीक्षण निदेशक नई दिल्ली और अन्य,-उत्तरदाता।

1987 की सिविल रिट याचिका संख्या 6460

30 मार्च, 1992

आयकर अधिनियम, 1961-धारा 132-आयकर नियम, 1962-तलाशी का आदेश देने की शक्ति-ऐसी शक्ति का उपयोग कानून के अनुसार सख्ती से किया जाना-फर्म ए के खिलाफ जारी खोज वारंट-फर्म बी के विशेषाधिकारों की खोज-भागीदारों के नाम वाले प्राधिकरण पत्र बी की पुष्टि करते हैं-ऐसी तलाशी की वैधता।

यह मानते हुए कि 1961 के अधिनियम की खंड 132 के तहत शक्ति का प्रयोग, कर-प्रार्थना करने वाले के अधिकारों, गोपनीयता और स्वतंत्रता पर एक गंभीर आक्रमण किया जाता है, शक्ति का प्रयोग कानून के अनुसार सख्ती से किया जाना चाहिए और केवल उन उद्देश्यों के लिए जिनके लिए कानून इसका प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है। यदि शक्ति की हमेशा के लिए दो शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है तो कार्यवाही रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगी।

(पैरा 12)

इसके अलावा, प्राधिकरण का वारंट फाइल में उल्लिखित सभी व्यक्तियों के परिसरों की तलाशी के लिए था। प्राधिकरण पत्र में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि ऐसे सभी व्यक्तियों और उनके परिसरों की तलाशी ली जा सकती है जिनका उल्लेख किया गया था। निर्धारित फर्म के भागीदारों द्वारा किए गए अन्य व्यवसायों के संबंध में लेखा पुस्तकें और अन्य दस्तावेज निश्चित रूप से प्रासंगिक होंगे क्योंकि वे लेनदेन और आपूर्ति सामग्री के बीच अंतर-संबंध को दर्शाते हैं जो फर्म द्वारा आयकर की चोरी के मामले में असर डालते हैं। तथ्य यह है कि अधिकारियों ने तलाशी ली थी और अन्य फर्मों और कंपनियों के नाम पर किए गए व्यवसाय के संबंध में लेखा पुस्तकों और दस्तावेजों को जब्त कर लिया था, इसलिए तलाशी को अवैध नहीं माना जा सकता था।

(पैरा 14)

बी. एस. गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता और संजय बंसल, अधिवक्ता याचिकाकर्ता के लिए।

आर. पी. साहनी, प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता आराधना साहनी के साथ अधिवक्ता

निर्णय

माननीय न्यायमूर्ति वी. के. बाली

(1) आयकर आयुक्त द्वारा 7 जुलाई, 1987 को आयकर अधिनियम, 1961 की खंड 132 और आयकर नियम, 1962 (इसके बाद क्रमशः 1961 के अधिनियम और 1962 के नियमों के रूप में संदर्भित) के नियम 112 (1) के तहत जारी किए गए प्राधिकरण के वानवरांटा के अनुसार, प्राधिकरण के उपरोक्त वारंट की अगली कड़ी की तलाशी और जब्ती के परिणामस्वरूप 4 किलोग्राम सोने के गहने, 119 किलोग्राम चांदी के गहने, 2 करोड़ रुपये की नकदी बरामद हुई। मैसर्स जय भगवान ओम प्रकाश ने आईडी1, पंचनामा तैयार करने (अनुलग्नक पी3), आभूषणों और अन्य वस्तुओं की सूची/सूची, साथ ही जब्त की गई नकदी की सूची, जब्त की गई खाता पुस्तकों की सूची/सूची और 1962 के नियम के नियम 112-ए के तहत नोटिस को चुनौती दी है, ओम प्रकाश, सोम प्रकाश, अविनाश चंद्र और विनय कुमार की साझेदारी वाली संस्था है। प्राधिकरण के वारंट और उक्त वारंट के बल पर शुरू की गई कार्यवाही को याचिकाकर्ता द्वारा पूरी तरह से अवैध और अधिकार क्षेत्र के बिना बताया गया है। यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता के परिसर की तलाशी के लिए प्राधिकरण का कोई वारंट नहीं था क्योंकि उक्त प्राधिकरण मैसर्स ओम प्रकाश सोम प्रकाश के खिलाफ था जो एक एचयूएफ निर्धारिती था। यह आगे कहा गया है कि जो आभूषण और नकदी मिली और जब्त की गई थी, वह निर्धारिती द्वारा रखी गई नियमित लेखा पुस्तकों में उल्लिखित है, जो स्वर्ण नियंत्रण रजिस्टर में प्रविष्टियाँ द्वारा समर्थित हैं, और यह भी कि छापा मारने वाले पक्ष के मन में परिसर के बारे में पूरी तरह से भ्रम था-जिसकी तलाशी प्राधिकरण के वारंट के अनुसरण में की जानी थी।

मैसर्स ओम प्रकाश सोम प्रकाश, याचिकाकर्ता मैसर्स जय भगवान, ओम प्रकाश को आयकर अधिनियम की खंड 185 के तहत एक पंजीकृत फर्म कहा गया है, और इसलिए मैसर्स ओम प्रकाश सोम प्रकाश के खिलाफ जारी किए गए प्राधिकरण के वारंट का उपयोग याचिकाकर्ता के परिसर की तलाशी के उद्देश्य से नहीं किया जा सका। हालाँकि, इस मामले को आयकर अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के आलोक में निपटाने द्वारा, पहले उन तथ्यों को स्पष्ट करना उपयोगी होगा, जिनके कारण याचिकाकर्ता को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत वर्तमान याचिका दायर करके उपरोक्त मुद्दे को उठाना आवश्यक हो गया है।

(2) मैसर्स जय भगवान ओम प्रकाश ऊपर बताए गए भागीदारों की जीकृत फर्म है। यह फर्म आयकर अधिनियम की खंड 185 के तहत और साझेदारी अधिनियम के तहत भी विधिवत पंजीकृत है। आय-कर अधिकारी, बी-वार्ड, करनाल द्वारा याचिकाकर्ता-फर्म का मूल्यांकन निर्धारण वर्ष 1986-87 तक किया गया था। 7 जुलाई, 1987 को मैसर्स ओम प्रकाश-सोम प्रकाश के परिसरों की तलाशी लेने के लिए अधिकृत अधिकारियों, अर्थात् सर्वश्री एस. पी. महाजन, आयकर अधिकारी, हिसार और एस. सी. सभरवाल, आयकर अधिकारी, रेवाड़ी के पक्ष में 1961 के अधिनियम की खंड 132 के तहत प्राधिकरण के वारंट जारी किए गए थे। याचिकाकर्ता-फर्म का मामला यह है कि मैसर्स ओम प्रकाश सोम प्रकाश के तलाशी अभियान को अंजाम देने के बजाय, जिस फर्म के परिसरों की तलाशी केवल प्राधिकरण के वारंट के अनुसार ली जानी थी, याचिकाकर्ता मैसर्स जय भगवान ओम प्रकाश के परिसर में कार्रवाई की गई थी। जहाँ तक फर्म मैसर्स ओम प्रकाश सोम प्रकाश का संबंध है, यह केवल एक एच. यू. पी. है और एच. यू. एफ. की स्थिति में धन-कर अधिनियम के तहत मूल्यांकन किए जाने के अलावा कोई भी व्यवसाय नहीं करता है। उपरोक्त एच. यू. एफ. से संबंधित निर्धारण वर्ष 1986-87 के संबंध में पारित संपत्ति-कर अधिनियम के तहत मूल्यांकन आदेश की एक प्रति इस याचिका के रिकॉर्ड में रखी गई है, और इसे पी. आई. के रूप में संलग्न किया गया है। एक पंचनामा तैयार किया गया था, जिसमें जय भगवान सोम प्रकाश, सराफा बाजार, करनाल के नाम और शैली के तहत व्यवसाय के संबंध में मैसर्स ओम प्रकाश सोम प्रकाश के नाम का उल्लेख किया गया था। याचिकाकर्ता के मामले के अनुसार, मैसर्स जय भगवान ओम प्रकाश के व्यवसाय के संबंध में प्राधिकरण के वारंट का कोई संकेत नहीं था। आभूषणों की एक सूची/सूची तैयार की गई थी, जिसमें मैसर्स जय भगवान ओम प्रकाश के रूप में व्यवसाय के संबंध में ओम प्रकाश सोम प्रकाश के नाम का उल्लेख किया गया था। याचिकाकर्ता के मामले के अनुसार, जिन वस्तुओं को कब्जे में लिया गया था और जिनकी एक सूची तैयार की गई थी, उनका उल्लेख याचिकाकर्ता के स्टॉक रजिस्टर में और स्वर्ण नियंत्रण रजिस्टर में भी मिलता है।

जिसे याचिकाकर्ता द्वारा नियमित रूप से चलाया जाता है। याचिकाकर्ता का मुख्य कार्य पत्थरों से जड़े सोने और सोने के आभूषणों के निर्माण और बिक्री के अलावा सोने और चांदी के आभूषणों के गिरवी रखने के खिलाफ अग्रिम धन देना है। बरामद और जब्त की गई नकदी की एक और सूची तैयार की गई थी, जिसमें ओम प्रकाश सोम प्रकाश का नाम मेसर्स भगवान दास सोम प्रकाश के व्यवसाय के रूप में उल्लेख किया गया है। उपरोक्त तरीके से, इस प्रकार, पंचनामे के साथ-साथ नकद प्रतिलिपि की सूची में भी अंतर है। 4 सोने के गहने और 119 किलोग्राम चांदी के गहने जब्त किए गए और परिसर में पाई गई कुल नकदी में से रु 1,32,173, रु. 1,25,000 जब्त कर लिया गया। लेखा पुस्तकें भी जब्त कर ली गईं, जिनमें से एक और सूची तैयार की गई थी। 30 जुलाई, 1987 को आयकर अधिकारी, ए-वार्ड, करनाल द्वारा ओम प्रकाश सोम प्रकाश, जोरियन कुआँ, करनाल के नाम पर 1962 के नियमों के नियम 112-ए के तहत एक नोटिस जारी किया गया था। उपरोक्त नोटिस का जवाब याचिकाकर्ता द्वारा 31 जुलाई, 1987 को भेजा गया था जिसमें उल्लेख किया गया था कि मेसर्स ओम प्रकाश सोम प्रकाश जोरियन कुआँ, करनाल में कोई व्यवसाय नहीं करते हैं और न ही यह कोई दुकान चलाता है और मेसर्स ओम प्रकाश सोम प्रकाश के किसी भी परिसर में 1961 के अधिनियम की खंड 132 के तहत कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। उपरोक्त उत्तर की प्राप्ति के तुरंत बाद, आयकर अधिकारी, बी-Ward, करनाल द्वारा 1962 के नियमों के नियम 112- ए के तहत एक नया नोटिस जारी किया गया था, जिसमें पाया गया और जब्त की गई संपत्ति और आभूषणों की व्याख्या करने के लिए लेखा पुस्तकें पेश करने या पेश करने के लिए कहा गया था। 6 अगस्त, 1987 को भी इस नोटिस पर एक जवाब भेजा गया था, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि इसमें कोई वारंट नहीं थे, मेसर्स जय भगवान ओम प्रकाश ने कहा कि याचिकाकर्ता के परिसर में की गई पूरी तलाशी अवैध थी और आयकर अधिकारी, ए-वार्ड, करनाल द्वारा 30 जुलाई, 1987 को जारी किए गए विभिन्न नोटिसों और आयकर अधिकारी, बी-वार्ड, करनाल द्वारा नोटिस का जवाब मिलने पर भेजे गए दूसरे नोटिस से यह स्पष्ट था कि याचिकाकर्ता के परिसर में तलाशी लेने का कोई औचित्य नहीं था। स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए, प्राधिकरण के वारंट की एक प्रति की मांग की गई थी। 16 अगस्त, 1987 को याचिकाकर्ता ने आयकर आयुक्त, रोहतक को एक पत्र संबोधित किया, जिसमें 1961 के अधिनियम की खंड 132 के प्रावधानों की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया गया और उन्हें उन तथ्यों से अवगत कराया गया जिनके तहत याचिकाकर्ता के मामले के अनुसार तलाशी और जब्ती अवैध थी। याचिकाकर्ता द्वारा संबंधित समय पर जब्त की गई सभी वस्तुओं को वापस करने की मांग की गई थी। उपरोक्त पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता-फर्म के नाम पर ऐसा कोई वारंट जारी नहीं किया गया था, और ऐसा होने पर, आयकर अधिकारियों के लिए ऐसा करने का कोई औचित्य नहीं था या तो माल जब्त कर लिया या उन्हें वापस करने से इनकार कर दिया। बाद में दिए गए अनुस्मारकों के बावजूद जब याचिकाकर्ता की शिकायत का आयकर अधिकारियों द्वारा निवारण नहीं किया गया था, तो वर्तमान रिट याचिका इस न्यायालय में दायर की गई थी।

(3) प्रतिवादी द्वारा एक लिखित बयान दायर करके इस याचिका का विरोध किया गया है, जिसमें प्रारंभिक आपत्तियों के माध्यम से यह कहा गया है कि वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता के कारण याचिका खारिज की जानी चाहिए, जिसका याचिकाकर्ता द्वारा लाभ नहीं उठाया गया है। यह कहा गया है कि खंड 132 (10) के तहत, और 1961 के अधिनियम की खंड 132 (11) के तहत भी, याचिकाकर्ता के पास अन्य दस्तावेजों की लेखा पुस्तकों को वापस करने और क्रमशः उक्त अधिनियम की खंड 132 (5) के तहत किए गए आदेश के संबंध में उपाय है, और यह कि भले ही वर्तमान याचिका में दावा की गई राहत के लिए कानून के तहत एक विशिष्ट उपाय प्रदान किया गया है, याचिकाकर्ता ने उक्त उपाय को मंजूरी देने का विकल्प चुना है; इस प्रकार, इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत इस न्यायालय से किसी भी राहत के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। प्रतिवादी का मामला गुण-दोष पर यह है कि जय भगवान ओम प्रकाश के रूप में शैलीबद्ध फर्म एक साझेदारी चिंता है, और इसमें दो भागीदार, ओम प्रकाश और सोम प्रकाश शामिल हैं, जिनके मूल्यांकन वर्ष 1985-86 तक समान शेर हैं। आयकर रिकॉर्ड के अनुसार, सर्वश्री अविनाश चंदेर और विजय कुमार को 1 अप्रैल, 1985 से मूल्यांकन वर्ष 1986-87 के लिए प्रासंगिक भागीदार के रूप में लिया गया था। फर्म को आयकर अधिनियम के तहत पंजीकृत फर्म के रूप में माना जाता है-26 सितंबर, 1986 के आदेश के अनुसार, और आयकर रिकॉर्ड पर यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि फर्म साझेदारी अधिनियम के तहत पंजीकृत है। यह आगे कहा गया है कि आय-कर अधिकारियों, यानी प्रतिवादी 3 और 4 को आय-कर अधिनियम की खंड 132 के तहत प्राधिकरण के वारंट जारी किए गए थे। याचिकाकर्ता ने कहा कि तलाशी वारंट मेसर्स ओम प्रकाश सोम प्रकाश, सराफा बाजार, कमल के व्यावसायिक परिसरों की तलाशी के लिए जारी किया गया था, न कि केवल ओम प्रकाश सोम प्रकाश परिसर की, जैसा कि याचिकाकर्ता ने कहा है। अधिकृत

अधिकारियों ने ओम प्रकाश सोम प्रकाश, सराफा बाजार, कमल के व्यावसायिक परिसरों की तलाशी ली, जिसकी तलाशी ली गई थी। यह भी कहा गया है कि किसी ने लिखित या मौखिक रूप से कोई विरोध दर्ज नहीं कराया था और किसी भी हिस्से से बिना किसी विरोध के तलाशी ली गई थी। प्राधिकरण का वारंट विधिवत श्री सोम प्रकाश को दिखाया गया, जिन्होंने उसी पर अपने हस्ताक्षर जोड़े और कार्यवाही के दौरान, सोम प्रकाश ने विशेष रूप से यह कहते हुए एक बयान दिया कि जिन व्यावसायिक परिसरों की तलाशी ली गई थी, उन्हें ओम प्रकाश सोमी प्रकाश द्वारा चलाया जा रहा था। यह भी कहा गया है कि व्यावसायिक परिसर मेसर्स ओम प्रकाश सोम प्रकाश द्वारा चलाया जा रहा है जो इस तथ्य से साबित होता है कि

तलाशी और जब्ती की कार्यवाही के दौरान, महादेव बॉम्बेवाला का एक बयान भी दर्ज किया गया था, जिसने स्पष्ट रूप से कहा था कि वह मेसर्स ओम प्रकाश सोम प्रकाश की ओर से चांदी पिघल रहा है। यह भी कहा गया है कि श्री ओम प्रकाश के पुत्र श्री कैलाश चंद के बयान के अनुसार, जो 2 मार्च, 1977 को अधीक्षक (रोकथाम) श्री जी. डी. थापर के समक्ष दर्ज किया गया था और शपथ पर किस बयान की पुष्टि की गई थी, यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि फर्म का नाम मेसर्स ओम प्रकाश सोम प्रकाश है और यह व्यवसाय पिछले 30 से 35 वर्षों से किया जा रहा है। कहा जाता है कि प्रतिवादी ने इस सूचना पर कार्रवाई की कि मेसर्स ओम प्रकाश सोम प्रकाश सराफा बाजार, कमल में सराफा का व्यवसाय कर रहे हैं। उपरोक्त स्थान की तलाशी छापा मारने वाले दल द्वारा पंचों की उपस्थिति में व्यवस्थित तरीके से की गई और तलाशी के दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। तलाशी के दौरान, अधिकृत, अधिकारियों ने पंचों की उपस्थिति में गंभीर पुष्टि पर सोम प्रकाश का बयान दर्ज किया। बयान को पढ़ा गया और श्री सोम प्रकाश को समझाया गया, जिन्होंने इसकी शुद्धता के प्रतीक के रूप में उस पर हस्ताक्षर किए और विशेष रूप से कहा कि उनका बयान सही तरीके से दर्ज किया गया था। तलाशी अभियान के दौरान सोम प्रकाश द्वारा दिए गए बयान के अवलोकन से यह पता चला कि यह व्यवसाय जय भगवान ओम प्रकाश, कमल के रूप में ओम प्रकाश द्वारा चलाया जा रहा था। इसी तथ्य के कारण जय भगवान ओम प्रकाश के नाम से व्यवसाय के संबंध में मेसर्स ओम प्रकाश सोम प्रकाश का नाम पंचनामे में उल्लिखित किया गया है। जहाँ तक लेखा पुस्तकों में पाई गई और उल्लिखित वस्तुओं के संबंध में याचिकाकर्ता के मामले का संबंध है, यह कहा गया है कि यह आत्यन्तिक रूप गलत है और यहां तक कि श्री सोम प्रकाश के बयान के अनुसार, जो तलाशी के दौरान अधिकृत अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया था, यह उनके द्वारा स्वीकार किया गया कि स्टॉक 16 जुलाई, 1987 को प्रतिबिंबित हुआ, रखे गए खातों की पुस्तकों के अनुसार, सोने के गहने रु 4, 88, 297.87, चांदी के पुराने आभूषणों की कीमत रु 34,500 था। जबकि चांदी के आभूषणों की कीमत रु 5, 345। उपरोक्त आभूषणों के अलावा, 2,10,282.89 रुपये के गहने गिरवी रखे गए। जैसा कि ऊपर दिया गया है, लेखा पुस्तकों में प्रतिबिंबित स्टॉक की तुलना में, परिसर की तलाशी के समय भौतिक सत्यापन पर निम्नलिखित स्टॉक पाए गए:

वस्तुओं के वजन की राशि

चांदी के आभूषण	1 क्यूटीएल 98 किलो।	(रु.)5,50,000
सोने के आभूषण	880 ग्राम। 6 किलोग्राम।	(रु.)16,00,000
हीरे के आभूषण	821 ग्राम।	(रु.) 20,000

श्री सोम प्रकाश, याचिकाकर्ता के इस दावे को कि लेखा पुस्तकों के अनुसार स्टॉक के साथ मिलान किया गया स्टॉक पाया गया है, तलाशी के दौरान स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया गया है। मेरे खाते में 4 लाख रुपये की अघोषित आय है। नकद और चांदी के आभूषणों के लिए, इस तेल को बाद में संशोधित कर रु 6 लाख, बयान के अनुसार अघोषित आय), सोने और चांदी के आभूषणों की थी। प्रतिवादी के मामले के अनुसार, यह निर्णायक रूप से स्थापित करता है कि खोज के दौरान पाया गया स्टॉक समझाया गया स्टॉक नहीं था। सोम प्रकाश ने अपने बयान में आगे स्वीकार किया, जिसका संदर्भ ऊपर दिया गया है, कि दुकान में एचयूएफ के सोने के

आभूषण नियमित लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं थे। जब उन्हें बताया गया कि तलाशी के दौरान मिले गहने नए गहने थे, न कि पुराने गहने, जो कथित रूप से एचयूएफ से संबंधित थे, तो श्री सोम प्रकाश ने कहा कि वह एचयूएफ से संबंधित सोने के गहने की पहचान करने में असमर्थ हैं। रिकॉर्ड के अनुसार, ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे पता चले कि एचयूएफ ने अपने आभूषणों को परिवर्तित कर दिया था। जहाँ तक 1962 के नियमों के नियम 112-ए के तहत जारी किए गए नोटिस का संबंध है, प्रतिवादी का मामला यह है कि जय भगवान ओम प्रकाश फर्म को जारी किए गए नोटिस में स्पष्ट रूप से मेसर्स ओम प्रकाश सोम प्रकाश के नाम का उल्लेख है। पंचनामा, आभूषणों की सूची आदि और लेखा पुस्तकों की सूची सभी पर श्री सोम प्रकाश ने हस्ताक्षर किए थे, जिसमें मेसर्स जय भगवान ओम प्रकाश के नाम और शैली के तहत व्यवसाय के संबंध में मेसर्स ओम प्रकाश सोम प्रकाश का नाम भी दिखाया गया है। इस तथ्य की पुष्टि मैसर्स ओम प्रकाश एंड संस, सराफा बाजार, कमल के व्यावसायिक परिसर से जब्त किए गए दस्तावेजों से होती है, जिसे याचिकाकर्ता की सहयोगी संस्था कहा जाता है, जिसमें "ओम प्रकाश सोम प्रकाश, सराफा का जामा और ओम प्रकाश सोम प्रकाश सराफा का नामा" शामिल हैं।" तलाशी और जब्ती के समय सोम प्रकाश द्वारा दिए गए बयान में, उनके द्वारा यह बताया गया था कि मैसर्स ओमी प्रकाश सोम प्रकाश द्वारा संचालित व्यवसाय को जय भगवान ओम प्रकाश के रूप में शैलीबद्ध किया गया है। उपरोक्त तथ्य को साबित करने के लिए, प्रतिवादी ने यह भी अनुरोध किया है कि मेसर्स ओम प्रकाश सोम प्रकाश पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों द्वारा जुर्माने के रूप में लगाए गए 3,500 रुपये को निर्धारण वर्ष 1974-75 के लिए मेसर्स जय भगवान ओम प्रकाश के लाभ और हानि खाते में डेबिट किया गया था। इसके अलावा, 3,250 रुपये का रिफंड, गोल्ड कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा अनुमत उपरोक्त दंड मेसर्स जय भगवान ओम प्रकाश के लाभ और हानि खाते में फिर से जमा किया। मैसर्स जय भगवान ओम प्रकाश के भागीदार के रूप में श्री ओम प्रकाश ने-6 जून, 1077 को आयकर अधिकारी को संबोधित अपने पत्र के माध्यम से, स्वयं अनुरोध किया था कि मैसर्स जय भगवान ओम प्रकाश को 5 लाख रुपये का रिफंड दिया जाए। लाभ और हानि खाते में जमा 3,250 को आय नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि 3,500 रुपये का जुर्माना पहले से ही अस्वीकृत थे। उपरोक्त तथ्यों के साथ-साथ सोम प्रकाश के आचरण से भी प्रतिवादी द्वारा कहा गया है कि यह स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया था कि तलाशी परिसर जय भगवान ओम प्रकाश के नाम और शैली में व्यवसाय के संबंध में मैसर्स ओम प्रकाश सोम प्रकाश द्वारा चलाया जा रहा था।

(4) ऊपर बताए गए तथ्यों से, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, श्री बी. एस. गुप्ता, जोरदार तर्क देते हैं कि याचिकाकर्ता के परिसरों की तलाशी के लिए प्राधिकरण का कोई वारंट नहीं था अर्थात् मेसर्स जय भगवान ओम प्रकाश और चूंकि प्राधिकरण के वारंट मेसर्स ओम प्रकाश सोम प्रकाश के खिलाफ थे, जो एक एच. यू. एफ. निर्धारित थे, शुरुआत से ही कार्यवाही पूरी तरह से अनधिकृत और अवैध थी। उन्होंने आगे तर्क दिया कि किसी भी मामले में, छापा मारने वाले पक्ष के मन में एक भ्रम था कि मैसर्स ओम प्रकाश सोम प्रकाश के परिसरों की तलाशी के लिए उन्हें जारी किए गए प्राधिकरण के वारंट के अनुसरण में किन परिसरों की तलाशी ली जानी चाहिए थी। उन्होंने आगे तर्क दिया कि न तो सक्षम अधिकारियों के समक्ष कोई जानकारी थी और न ही दिमाग का कोई आवेदन था और जानकारी की अनुपस्थिति में और दिमाग का उपयोग न आदेश के कारण जारी किए गए प्राधिकरण के वारंट प्राधिकरण के वारंट के क्रम को ही दूषित कर देंगे और बाद की कार्यवाही भी जो बाद में ली गई है। वैकल्पिक रूप से, विद्वान अधिवक्ता यह भी तर्क देता है कि भले ही सक्षम अधिकारियों के पास जानकारी उपलब्ध थी और दिमाग का उपयोग किया गया था, फिर भी उन सभी तथ्यों और परिस्थितियों को याचिकाकर्ता को सूचित करने की आवश्यकता थी जिनके कारण तलाशी और जब्ती के लिए वारंट जारी करने के संबंध में एक आदेश पारित करने की आवश्यकता थी, साथ ही जिस आधार पर कार्यवाही शुरू हुई थी, ताकि विभाग के मामले को ठीक से पूरा किया जा सके और लिखित बयान में कुछ भी खुलासा नहीं किया गया है, यह माना जाएगा कि 1961 के अधिनियम की खंड 132 के तहत परिकल्पित तलाशी और जब्ती करने के लिए बहुत आवश्यक चीजों का अभाव था।

(5) दूसरी ओर, प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री आर. पी. साहनी उन सभी तर्कों का खंडन करते हैं जो ऊपर देखे गए हैं। इस सवाल पर कि प्राधिकरण का वारंट मैसर्स ओम प्रकाश सोम प्रकाश के नाम था, जबकि जय भगवान ओम प्रकाश के व्यावसायिक परिसर की तलाशी ली गई थी, विभाग का मामला, जैसा कि श्री साहनी ने रखा है, यह है कि सराफा बाजार, करनाल में किया जा रहा वास्तविक व्यवसाय ओम प्रकाश सोम प्रकाश है, और जय भगवान ओम प्रकाश फर्म का नाम केवल एक छलावा है। वह आगे तर्क देता है कि पहले प्राधिकरण का वारंट सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया था, विभाग के पास पर्याप्त जानकारी उपलब्ध

थी और प्रामाणिक विश्वास पर, अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि निर्धारिती के पास धन, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तुएं थीं, जिनका खुलासा आयकर अधिनियम के उद्देश्य से नहीं किया गया था। जहाँ तक याचिकाकर्ता के वकील का तर्क है कि विभाग के पास उपलब्ध जानकारी के संबंध में याचिका में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है, और जिस सामग्री पर अधिकारियों को वास्तविक विश्वास था, श्री साहनी का तर्क है कि पूरी याचिका में उपलब्ध सामग्री पर कोई राय नहीं होने के संबंध में एक भी शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था, और इसलिए, लिखित बयान में इसका खुलासा करना संभव नहीं था। हालांकि, उनका तर्क है कि अदालत के कहने पर, प्राधिकरण के वारंट जारी करने के आदेश में समाप्त होने वाली पूरी फाइल को पेश किया जा सकता है और वास्तव में, बहस के दौरान, इसे अदालत के अवलोकन के लिए पेश किया गया था।

(6) पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, हमारी राय है कि जब तक प्राधिकरण का वारंट जारी करते समय याचिकाकर्ता के मामले से संबंधित प्रासंगिक फाइल का अध्ययन नहीं किया गया है, तब तक वर्तमान मामले में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना मुश्किल होगा। हालांकि, ऐसा करने से पहले, इस स्तर पर 1961 के अधिनियम की खंड 132 के प्रावधानों को निकालना भी उपयोगी होगा, जहाँ तक उनका वर्तमान मामले के तथ्यों पर असर है। खंड 132 का प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार है:—

“132. (1) जहां निरीक्षण निदेशक या आयुक्त (या निरीक्षण या निरीक्षण सहायक आयुक्त का कोई ऐसा उप निदेशक जो बोर्ड द्वारा इस संबंध में सशक्त किया जाए, उसके पास मौजूद जानकारी के परिणामस्वरूप यह विश्वास करने का कारण है कि –

(सी) “ किसी व्यक्ति के पास कोई धन, सर्राफा, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या वस्तु है और ऐसा धन, सर्राफा, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या वस्तु या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से आय या संपत्ति का प्रतिनिधित्व करती है जिसका भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या इस अधिनियम (इसके बाद इस खंड में संपत्ति की अघोषित आय के रूप में संदर्भित) के प्रयोजनों के लिए खुलासा नहीं किया गया है या नहीं किया जाएगा”।

(ऐ) निरीक्षण निदेशक या आयुक्त, जैसा भी मामला हो, किसी भी निरीक्षण उप निदेशक, निरीक्षण सहायक आयुक्त, निरीक्षण सहायक निदेशक या आयकर अधिकारी को अधिकृत कर सकता है, या

(1) किसी भी इमारत, स्थान, पोत, वाहन या विमान में प्रवेश करें और तलाशी लें, जहां उसे संदेह करने का कारण है कि ऐसी लेखा बहियां, अन्य दस्तावेज, धन, सोना-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या वस्तु रखी गई है।

(7) संबंधित वारंट जारी करने के संबंध में याचिकाकर्ता से संबंधित फाइल, ए. डी. आई. द्वारा 9 मार्च, 1987 के एक नोट से शुरू होती है, जिसमें कहा गया है कि मैसर्स ओम प्रकाश सोम प्रकाश सराफ, ओल्ड सराफा बाजार, करनाल के खिलाफ एक शिकायत पर, शिकायतकर्ता उपस्थित हुआ था और उसे दल के शेलर और आवासीय परिसरों के स्थान के बारे में अधिक जानकारी एकत्र करने के लिए कहा गया था। अधिकारी द्वारा आगे कहा गया है कि वह 30 मार्च, 1986 को करनाल जा रहे थे और एक विशेष स्थान और विशेष समय पर शिकायतकर्ता से मिलेंगे और पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद फाइल को फिर से जमा किया जाएगा। फाइल पर अगला उपलब्ध 3 अप्रैल 1987 का है। जिसमें कहा गया है कि मैसर्स ओम प्रकाश सोम प्रकाश सराफ, ओल्ड सराफा बाजार, करनाल से संबंधित फाइल उस व्यक्ति को सौंप दी गई है जिसने बनाया था और शिकायतकर्ता ने ओम प्रकाश सोम प्रकाश और उसके सहयोगियों के खिलाफ विभिन्न आरोप लगाए थे।

शिकायतकर्ता ने कहा कि ओम प्रकाश सोम प्रकाश की दुकान सराफा बाजार में थी। श्री ओम प्रकाश के परिवार के अन्य सदस्य भी करनाल में सराफा का व्यवसाय कर रहे थे। इन व्यक्तियों में श्री ओम प्रकाश के भाई श्री प्रेम चंद सराफ और गुप्ता फोटोग्राफर, श्री ओम प्रकाश के बेटे श्री भगत राम उपनाम भगत सराफ शामिल थे। कहा जाता है कि श्री ओम परी-आश पर भी ओम प्रकाश नाम का एक लेखाकार होने का आरोप है जिनके घर में दस्तावेज और सामान पड़े हुए हैं। यह आगे कहा गया है कि नोट बनाने वाले अधिकारी के अनुसार इन व्यक्तियों ने भारी संपत्ति अर्जित की है और करोड़ों में आय अर्जित की है। पता चलता है कि सोने और चांदी के आभूषणों के अलावा करोड़ों की नकदी उनके पास पड़ी है। उन्हें करनाल के पास अपने चावल के गोले और पर्याप्त मात्रा में जमीन मिली है। करनाल के कुनीपुरा रोड पर उनकी तीन दुकानें भी हैं, जिन्हें किराए पर दिया गया है। इन प्रतिपुत्रों के खिलाफ शिकायतकर्ता द्वारा लगाया गया दूसरा आरोप यह था कि उन्हें चोरी की वस्तुओं को खरीदने की आदत थी और धन उधार देने में भी काम कर रहे थे। विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर खार्ते होने के अलावा कई बैंक लॉकर भी थे। यह भी कहा गया है कि इन व्यक्तियों के पास हीरे और सोने/चांदी के आभूषणों के अलावा कम से कम दो करोड़ रुपये नकद हैं। नोट बनाने वाले अधिकारी के अनुसार यह एक ऐसा मामला था जिसमें आयकर अधिनियम की खंड 132 के तहत आदेश पारित करने की आवश्यकता थी। शिकायतकर्ता ने व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों का पूरा विवरण दिया था और मामले में अधिक जानकारी की आवश्यकता थी। शिकायतकर्ता को एक बार फिर बुलाया गया और 8 अप्रैल, 1987 के नोट के अनुसार, उन्होंने ओम प्रकाश सोम प्रकाश, करनाल के खिलाफ लगाए गए आरोपों को जोरदार तरीके से दोहराया। उन्हें और जानकारी एकत्र करने के लिए कहा गया था। इसके बाद एक विस्तृत नोट है, जिसे 16 अप्रैल, 1987 को बनाया गया था। यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि इस मामले को उस तारीख से निपटाया गया है जब निरीक्षण के सहायक निदेशक को 9 मार्च, 1987 की लिखित शिकायत प्राप्त हुई थी। यह शिकायत परिवार के लोगों के एक समूह के खिलाफ थी। निम्नलिखित व्यक्तियों के खिलाफ कर चोरी के आरोप लगाए गए थे:—

1. मेसर्स ओम प्रकाश सोम प्रकाश, ओल्ड सराफा बाजार, करनाल;
2. श्री प्रेम चंद सराफ (श्री ओम प्रकाश के भाई);
3. श्री ओम प्रकाश के पुत्र श्री भगत राम उपनाम भगत;
4. गुप्ता फोटोग्राफर (श्री ओम प्रकाश के भाई);
5. श्री ओम प्रकाश सोम प्रकाश के लेखाकार ओम प्रकाश।

शिकायत में लगाए गए आरोप उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा करोड़ों की भारी संपत्ति जमा करने के संबंध में थे, जो उन्होंने बिना हिसाब के सोने और चांदी के आभूषणों का व्यवसाय करके अर्जित की है। नोट में शिकायतकर्ता के साथ विभिन्न बैठकों और उन व्यक्तियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की गंभीरता का भी नोट किया गया है, जिनका नोट ऊपर किया गया है। मामला केवल वहीं नहीं छोड़ा गया था और इस पर निरीक्षण के उप निदेशक के साथ चर्चा की गई थी और यहां तक कि ध्या नोट बनाने वाला व्यक्ति भी शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों की शुद्धता और सच्चाई का सत्यापन करने और पता लगाने के लिए खुद करनाल गया था। करनाल जाने और विभिन्न लोगों से मिलने और आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न स्थानों पर जाने के विवरण का भी उल्लेख किया गया है। संबंधित अधिकारी ने उन विभिन्न सूचनाओं का भी उल्लेख किया है जो उन्हें विभिन्न व्यक्तियों से उपलब्ध कराई गई थीं -

उनके स्वामित्व वाली संपत्तियों का विवरण भी उल्लेख किया गया है, जो संबंधित अधिकारी द्वारा मामले में व्यक्तिगत पूछताछ करके पाया गया था। अधिकारी ने यह दर्ज करते हुए अपना आकलन किया कि यह स्पष्ट था कि इन व्यक्तियों ने विभाग को अपनी वास्तविक और पूर्ण आय का खुलासा नहीं किया था और उनके द्वारा भारी कर चोरी की गई थी। वे खार्तों और दस्तावेजों की आपत्तिजनक पुस्तकों के अलावा लाखों रुपये की नकदी, कीमती सोना आदि रख रहे थे। उपरोक्त नोट में उल्लिखित व्यक्तियों की सूची इस प्रकार है:—

1. श्री ओम प्रकाश सी/ओ मेसर्स ओम प्रकाश सोम प्रकाश।
2. श्री सोम प्रकाश सी/ओ-ऊपर के रूप में -
3. श्री प्रेम चंद सराफ
4. ओम प्रकाश के पुत्र श्री भगत राम उपनाम भगत।

5. मेसर्स ओम प्रकाश सोम प्रकाश, सराफा बाजार, करनाल।
6. मेसर्स ओम प्रकाश सराफ एंड संस, सराफा बाजार, करनाल।
7. श्री प्रेम चंद और श्री भगत राम का व्यावसायिक सरोकार।
8. इन व्यक्तियों द्वारा लेखा पुस्तकें और कीमती सामान गुप्ता फोटोग्राफर, सराफा बाजार, करनाल नामक दुकान और श्री मदन लाल खाते के आवास में रखे जाते हैं।
9. मेसर्स हरियाणा कोल्ड स्टोर, हांसी रोड, करनाल।

अंतिम विश्लेषण में यह उल्लेख किया गया है कि यह मामला 1961 के अधिनियम की खंड 132 के तहत कार्रवाई के लिए परिपक्व था, और अनुमोदन प्राधिकरण पर तैयार किया जाना चाहिए और मामले को खोज के लिए रखा जाना चाहिए 23 अप्रैल, 1987 का एक और नोट है, जिसमें यह नोट किया गया है कि इस मामले पर आयकर आयुक्त, रोहतक और निरीक्षण उप निदेशक, रोहतक के साथ चर्चा की गई थी और आयकर आयुक्त के निर्देश के अनुसार, नोट बनाने वाले संबंधित अधिकारी ने आगे की पूछताछ करने के लिए 22 अप्रैल, 1987 को करनाल का दौरा किया था। उपरोक्त नोट के अनुसार, आगे की पूछताछ भी की गई, जिसने अधिकारी के विचार को दोहराया कि तलाशी ली जानी चाहिए। सम तिथि के एक अन्य नोट के अनुसार, मामले पर निरीक्षण निदेशक, नई दिल्ली और निरीक्षण उप निदेशक, रोहतक के साथ चर्चा की गई थी और ऐसा प्रतीत होता है कि हुई चर्चा के अनुसार, अधिकारी को उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा भूमि की खरीद के संबंध में आगे की पूछताछ करनी थी। 25 अप्रैल, 1987 के नोट के अनुसार, 25 अप्रैल, 1987 को करनाल का दौरा करके आगे की पूछताछ की गई और पूछताछ से पता चला कि व्यक्तियों के इस समूह ने कुछ साल पहले जमीन खरीदी थी और उन्होंने उक्त जमीन की खरीद में काला धन निवेश किया था।

भूमि उप निदेशक निरीक्षण ने 27 मई, 1987 को एक और नोट की, जिसमें यह दर्ज किया गया है कि पूर्ववर्ती पैरा में बताए गए तथ्यों का अध्ययन किया गया था और शिकायतकर्ता ने निम्नलिखित व्यक्तियों के खिलाफ आरोप लगाए थे:—

1. श्री ओम प्रकाश, निवास-शीश महल, कमल।
2. श्री सोम प्रकाश, निवास-जोरीन कुआँ, करनाल, सेवक संघ के पास।
3. श्री भगत राम उपनाम भगतु पुत्र श्री ओम प्रकाश-निवास-चौरा बाजार, करनाल।
4. श्री परवीन कुमार, निवास-जोरियन कुआँ, करनाल सी/ओ श्री प्रेम चंद।
5. श्री ज्ञान चंद, निवास-जोरियन कुआँ, करनाल।
6. मदन लाई, लेखाकार
7. मेसर्स ओम प्रकाश सोम प्रकाश, सराफा बाजार, कमल।
8. मेसर्स ओम प्रकाश एंड संस, सराफा बाजार, कमल।
9. श्री भगत राम उपनाम भगतु सराफा बाजार, कमल का व्यावसायिक परिसर।
10. श्री परवीन कुमार पुत्र श्री प्रेम चंद का व्यावसायिक परिसर, सराफा बाजार, करनाल।
11. मेसर्स गुप्ता फोटोग्राफर, सराफा बाजार, करनाल।
12. हरियाणा कोल्ड स्टोरेज, हांसी रोड, करनाल।

उपरोक्त नोट में यह भी नोट किया गया है कि आरोपों के संबंध में प्रकृति और साक्ष्य का नोट संलग्नक 'ए' में अलग से किया गया है। उपरोक्त संलग्नक चोरी किए गए आभूषणों की खरीद और खाता बही के बाहर सोने के आभूषणों की खरीद और बिक्री, गिरवी रखने के व्यवसाय के दौरान मालिकों को गिरवी रखे गए आभूषणों को जारी नहीं करना, बड़ी मात्रा में सोना और चांदी (लगभग 20 से 25 किलोग्राम सोना), उच्च दरों पर भूमि की खरीद और कम दरों पर बिक्री दर्ज कराना, लाखों में बेनामी नकदी, बैंकों में लॉकर होना, सोने के व्यवसाय और अन्य व्यवसाय के लिए खातों के डुप्लिकेट सेट का रखरखाव, और कोल्ड स्टोरेज व्यवसाय (हरियाणा कोल्ड स्टोरेज, हांसी रोड, कमल) में निवेश करने से संबंधित आरोपों से संबंधित है। सत्यापन के परिणाम को अलग से नोट किया गया है और यह उल्लेख किया गया है कि ए. डी. आई. द्वारा विभिन्न वर्गों से स्वतंत्र रूप से गुप्त पूछताछ की गई है और व्यवसाय की प्रकृति के संबंध में आरोप लगाए गए हैं।

उपरोक्त व्यक्तियों के पास नकदी की उपलब्धता संतोषजनक पाई गई। उपरोक्त नोट में यह नोट किया गया है कि भूमि की खरीद के संबंध में उनके सभी आरोप, और भूमि के एक टुकड़े के संबंध में विचार के कम आकलन को काफी हद तक सही पाया गया था, और भूमि के अन्य दो टुकड़ों के संबंध में, आरोपों को गुप्त पूछताछ से विशेष रूप से सत्यापित नहीं किया जा सका, और संदेह से बचने के लिए विस्तृत पूछताछ नहीं की गई थी, लेकिन लोगों को यह धारणा थी कि उपरोक्त व्यक्तियों के पास बहुत अधिक अघोषित धन था, जिसे वे भूमि की खरीद में निवेश करते हैं। उपरोक्त नोट में यह भी नोट किया गया है कि उपरोक्त पक्ष सभ्य और अच्छी तरह से निर्मित घरों में रह रहे थे और व्यवसाय के व्यस्त अनुसूची थे, साथ ही खंड 132 (1) (सी) में उल्लिखित शर्तें, यानी उनके पास नकदी, आभूषण और अन्य मूल्यवान वस्तुएं हैं, जिनका लेखा-जोखा नहीं किया गया था और जिनका विभाग को खुलासा नहीं किया गया था। व्यवसाय के वास्तविक संचालन में शामिल परिवार के सदस्यों के विवरण के संबंध में, यह उल्लेख किया गया है कि इस मामले पर ए. डी. आई. द्वारा विभिन्न पूर्ववर्ती पृष्ठों पर चर्चा की गई है, और इसलिए, खोज किए जाने वाले परिसरों के विवरण का उल्लेख फाइल के क्रम संख्या 1 से 12 तक पृष्ठ 21 पर किया गया है। इसके बाद फाइल को आयुक्त के समक्ष रखा गया। आयुक्त ने 7 जुलाई, 1987 के अपने आदेश पर हस्ताक्षर किए जिनका उल्लेख नीचे किया गया है:—

“मैंने शिकायत और सूचना देने वाले के बयान का अध्ययन किया है (सूचना देने वाले का नाम भी उल्लेख किया गया है लेकिन इस फैसले में उल्लेख किए जाने के लिए विशेष रूप से अनदेखी की जा रही है)। ए. डी. आई. और डी. डी. जे. द्वारा की गई पूछताछ की रिपोर्ट से पता चलता है कि जिन करदाताओं के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं, वे सोने, चांदी आदि में पर्याप्त व्यापार कर रहे हैं और उनके पास बेनामी आय और संपत्ति होने की संभावना है। की गई पूछताछ को ध्यान में रखते हुए, मेरे पास यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसी आय, संपत्ति आदि और संबंधित दस्तावेज केवल मूल्यांकन उद्देश्यों के लिए उपलब्ध होंगे, यदि आयकर अधिनियम, 1961 की खंड 132 के तहत तलाशी और जब्ती अभियान चलाया जाता है। तदनुसार, यह खोज के लिए एक उपयुक्त मामला है।

(8) कवर किए जाने वाले परिसर इन नोटों के पृष्ठ 21 पर सूची के अनुसार हैं। आवश्यक प्राधिकरण जारी किया गया।” 14 जुलाई, 1987 के नोट के अनुसार फतेहाबाद आदि में आतंकवादियों द्वारा सामूहिक हत्याओं के परिणामस्वरूप हरियाणा के शहरों में असामान्य स्थिति के कारण तलाशी नहीं ली जा सकी। यह नोट किया गया है कि कार्रवाई अनुसूची के अनुसार नहीं की जा सकी। यह स्पष्ट है कि इसके बाद जुलाई, 1987 को तलाशी और जब्ती अभियान चलाया गया था।

(9) तलाशी अभियान के अस्तित्व में आने के तरीके और तरीके की जांच करने के बाद, इस स्तर पर यह पता लगाना उचित होगा कि 1961 के अधिनियम की खंड 132 के तहत की जाने वाली कार्रवाई के लिए किस प्रक्रिया का पालन किया जाना आवश्यक है। इस तरह की प्रक्रिया को 1962 के नियमों के नियम 112 के प्रावधानों के तहत विस्तृत रूप से निर्धारित किया गया है। उप-नियम (2), (2ए), (3), (4बी), (5), (6), (7) और (9), जिनका वर्तमान मामले में निर्णय लेने के लिए आवश्यक विवाद पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है, निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:—

“(2) (क) महानिदेशक या निदेशक या मुख्य आयुक्त या आयुक्त या किसी ऐसे उप निदेशक या उपायुक्त द्वारा खंड 132 की खंड (1) के तहत प्राधिकरण (उसके परंतुक के तहत प्राधिकरण के अलावा) जो बोर्ड द्वारा इस संबंध में सशक्त किया गया है, प्रपत्र संख्या 45 में होगा।

(ए) खंड 132 की उप-खंड (1) के तहत मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राधिकरण प्रपत्र संख्या 45ए में होगा।

(बी) मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा खंड 132 की उप-खंड (1ए) के तहत प्राधिकरण प्रपत्र संख्या 45बी में होगा।

(2क) उपनियम (2) में निर्दिष्ट प्रत्येक प्राधिकरण प्राधिकरण जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर के तहत लिखित रूप में होगा और उस पर उसकी मुहर लगेगी।

(3) तलाशी के लिए अधिकृत किसी भी भवन, स्थान, पोत, वाहन या विमान का या उसमें प्रभारी कोई भी व्यक्ति, अधिकारी की मांग पर, खंड 132 (इसके बाद अधिकृत अधिकारी के रूप में संदर्भित) के तहत तलाशी और जब्ती की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत होगा और प्राधिकरण को पेश करने पर, उसे उसमें स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने की अनुमति देगा और उसमें तलाशी के लिए सभी उचित सुविधाओं का खर्च उठाएगा।

(4) प्राधिकृत अधिकारी किसी भी व्यक्ति से, जो ऐसी इमारत, स्थान, पोत, वाहन या विमान में स्थित किसी बॉक्स, लॉकर, सेफ, अलमारी या किसी अन्य पात्र का मालिक है, या जिसके पास तत्काल कब्जा या नियंत्रण है, उसे खोलने और इसकी सामग्री की जांच करने के लिए निरीक्षण करने की अनुमति देने की आवश्यकता हो सकती है, और, जहां इसकी चाबियाँ उपलब्ध नहीं हैं या जहां ऐसा व्यक्ति ऐसे किसी भी पात्र का पालन करने में विफल रहता है,

ऐसे डिब्बे, लॉकर, सेफ, अलमारी या अन्य पात्र को तोड़ने सहित कोई भी कार्रवाई की जा सकती है जिसे अधिकृत अधिकारी उपनियम (2) के तहत जारी प्राधिकरण में निर्दिष्ट सभी या किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक समझ सकता है।

(5) खंड 132 की खंड (1) के खंड (आई. आई. ए.) में निर्दिष्ट किसी भी व्यक्ति की अधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसी सहायता के साथ तलाशी ली जा सकती है जो वह आवश्यक समझे। यदि ऐसा व्यक्ति एक महिला है, तो शालीनता को ध्यान में रखते हुए किसी अन्य महिला द्वारा तलाशी ली जाएगी।

(च) तलाशी लेने से पहले, अधिकृत अधिकारी

- (a) जहाँ किसी भवन या स्थान की तलाशी ली जानी है, वहाँ उस इलाके के दो या दो से अधिक सम्मानित निवासियों को बुलाएँ जहाँ उस भवन या स्थान की तलाशी ली जानी है, और
- (b) जहाँ किसी पोत, वाहन या विमान की तलाशी ली जानी है, वहाँ किसी भी दो या दो से अधिक सम्मानित व्यक्तियों को खोज में भाग लेने और देखने के लिए बुलाएँ और उन्हें या उनमें से किसी को ऐसा करने के लिए लिखित रूप में एक या एक आदेश जारी कर सकते हैं।

(7) तलाशी उपरोक्त गवाहों की उपस्थिति में की जाएगी और ऐसी तलाशी के दौरान जब्त की गई सभी चीजों की सूची और जिन स्थानों पर वे पाए गए थे, उनकी सूची क्रमशः अधिकृत अधिकारी द्वारा तैयार की जाएगी और ऐसे गवाहों द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी; लेकिन तलाशी देखने वाले किसी भी व्यक्ति को भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही में तलाशी के गवाह के रूप में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी, जब तक कि विशेष रूप से तलब नहीं किया जाता है।

(9) जहां किसी व्यक्ति की खंड 132 की उप-खंड (1) के खंड (आई. आई. ए.) के तहत तलाशी ली जाती है, वहां कब्जे में ली गई सभी चीजों की एक सूची तैयार की जाएगी और उसकी एक प्रति ऐसे व्यक्ति को दी जाएगी। इसकी एक प्रति मुख्य आयुक्त या आयुक्त को भेजी जाएगी, और जहां मुख्य आयुक्त के अलावा किसी अन्य अधिकारी द्वारा प्राधिकरण जारी किया गया है, वहां उस अधिकारी को भी भेजा जाएगा।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाई गई दलीलों की जांच करने का अब समय आ गया है

1961 के अधिनियम की खंड 132 और 1962 के नियमों के नियम 112 के प्रावधानों के तहत परिकल्पित पूर्ववर्ती शर्तान्तिक रूप पर, यह स्पष्ट करने की कोशिश की जाती है कि अधिकारियों के पास न आत्यन्तिक रूप कोई जानकारी उपलब्ध थी और न ही उपलब्ध जानकारी पर, अधिकारियों ने अपना दिमाग लगाया था। उपरोक्त तर्क को आयकर अधिकारी, विशेष जांच सर्कल "बी", मेरठ बनाम सेठ ब्रदर्स और अन्य (1969) 74 आई.टी.आर. 836 एस.सी.), एच. एल. सिबबल बनाम आयकर आयुक्त, पंजाब और अन्य (1975) 101 आई.टी.आर. 112.), (इस न्यायालय के डी. बी.) में दिए गए न्यायिक पूर्व निर्णय पर आधारित करने का प्रयास किया जाता है। जगमोहन महाजन और एक अन्य बनाम आयकर आयुक्त, पंजाब और अन्य:3 ((1976) 103 आई.टी.आर. 579.), ((डी. बी. इस न्यायालय में); मनमोहन कृष्ण महाजन बनाम आयकर आयुक्त, पटियाला, और अन्य ((1977) 107 आई.टी.आर., 400.), बलवंत सिंह और अन्य बनाम आर. डी. शाह, निरीक्षण निदेशक, आयकर, नई दिल्ली, और अन्य ((1969) 71 आई.टी.आर. 550.), पूरन माई बनाम निरीक्षण निदेशक (जांच), आयकर, नई दिल्ली, और अन्य ((1974) 93 आई.टी.आर. 505.), और इक्विटेबल इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड बनाम आयकर अधिकारी, जी. वार्ड और अन्य ((1988) 174 आई.टी.आर. 714.)। यहां यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि ऊपर उल्लिखित निर्णयों में से, प्रतिवादी ने ओटोन प्रकाश जिंदल पर भी भरोसा किया है। भारत और अन्य का संघ ((1976) 104 आई.टी.आर. 389.), और इक्विटेबल आई. आर. इन्वेस्टमेंट पर (ऊपर)। पूरन माई के मामले (ऊपर) में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि 1961 के अधिनियम की खंड 132 और 1962 के नियमों के नियम 112 के तहत परिकल्पित तलाशी और जब्ती से संबंधित प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (एफ) और (जी) के तहत मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं करते हैं, और यह कि खंड 132, खंड 132 A या नियम 112 A के किसी भी प्रावधान द्वारा लगाए गए प्रतिबंध भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (एफ) और (जी) के तहत स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध हैं। यह भी माना गया कि उक्त प्रावधान भी भेदभावपूर्ण नहीं हैं, और इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन नहीं करते हैं। इस मामले पर विचार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि:—

“(i) खंड के प्रावधान 132 स्पष्ट रूप से उन व्यक्तियों के खिलाफ निर्देशित किए जाते हैं जिन्हें अच्छे आधार पर माना जाता है, अवैध रूप से अपनी आय और संपत्ति पर कर के भुगतान से बच गए हैं। इसलिए सरकारी बकाया की वसूली के लिए ऐसी आय और संपत्ति प्राप्त करने के लिए कठोर उपाय अपने आप में उचित होंगे। जब किसी को अनुच्छेद 19 (1) (एफ) और (छ) में उल्लिखित स्वतंत्रताओं पर लगाए गए प्रतिबंधों या प्रतिबंधों की तर्कसंगतता पर विचार करना पड़ता है, तो कोई भी संभवतः इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता है कि इस तरह की चूक समुदाय के आर्थिक जीवन के महत्वपूर्ण अंगों को कैसे खा जाती है। यह हमारे आर्थिक जीवन का एक सर्वविदित तथ्य है कि बड़ी मात्रा में बेनामी धन परिसंचरण में है जो इसके ताने-बाने को खतरे में डाल रहा है। जिस देश ने कराधान की उच्च दरों को अपनाया है, वहां बेनामी धन का एक बड़ा हिस्सा आम तौर पर सरकारी खजाने में भरना चाहिए। ऐसा करने के बजाय यह अर्थव्यवस्था को विकृत करता है। इसलिए, समुदाय के हित में यह सही है कि वित्तीय प्राधिकरणों के पास कर चोरी को रोकने के लिए पर्याप्त शक्तियां होनी चाहिए।

(ii) तलाशी और जब्ती उन लोगों के शस्त्रागार में कोई नया हथियार नहीं है जिनका कर्तव्य अपने व्यापक अर्थों में सामाजिक सुरक्षा बनाए रखना है। इस प्रक्रिया को सभी सभ्य देशों में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है।

(iii) बड़े पैमाने पर कर चोरी को रोकने के लिए जब इसे आयकर अधिकारियों को सौंपा जाता है तो तलाशी और जब्ती के उपाय को चुनौती देने में अब बहुत देर हो चुकी होती है। वास्तव में, यह उपाय आपत्तिजनक होगा यदि इसके कार्यान्वयन के साथ इसके अनुचित और अनुचित अभ्यास के खिलाफ सुरक्षा उपाय नहीं हैं। एक व्यापक प्रस्ताव के रूप में अब यह कहना संभव है कि यदि सुरक्षा उपाय आम तौर पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की तर्ज पर अपनाए जाते हैं तो उन्हें पर्याप्त माना जाएगा और उपाय द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को उचित माना जाएगा।”

हालांकि, यह देखा गया कि हालांकि एक बहुत ही दुर्लभ मामले में एक कर-चोर एक मांग का पालन कर सकता है, निरीक्षण निदेशक जिसके पास विश्वसनीय जानकारी है कि निर्धारिती ने कुछ वित्तीय सौदों से प्राप्त अपनी आय को लगातार छुपाया है, इस उचित विश्वास को स्वीकार करने में उचित हो सकता है कि निर्धारिती। यदि आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है, तो वे उन्हें प्रस्तुत नहीं करेंगे। इस प्रकार, यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सक्षम अधिकारियों के समक्ष एक विश्वसनीय जानकारी होनी चाहिए और तलाशी और जब्ती का उपाय आपत्तिजनक होगा यदि इसके कार्यान्वयन के साथ इसके अनुचित और अनुचित के खिलाफ सुरक्षा उपाय नहीं हैं। उद्धृत अन्य निर्णयों को पढ़ने से और जिनका एक संदर्भ ऊपर दिया गया है, यह भी स्पष्ट है कि आयुक्त को अधिनियम की खंड 132 के तहत कार्य करते हुए ऐसे वारंट जारी करने के कठोर उपायों का सहारा लेने से पहले कुछ सामग्री अपने कब्जे में लेनी चाहिए। इस मामले में यह पर्याप्त रूप से स्पष्ट किया गया है कि अधिकारियों के समक्ष एक आवश्यक जानकारी थी, और न केवल यह कि विभाग ने अपने सामने उपलब्ध जानकारी की प्रामाणिकता के संबंध में खुद को पूरी तरह से संतुष्ट किया था, बल्कि समय-समय पर मामले की स्वतंत्र जांच भी की थी। जैसा कि अधिकारियों द्वारा चर्चा की गई है, जैसा कि स्पष्ट रूप से बताया गया है! ऊपर दिए गए तथ्यों का वर्णन और यह केवल तभी किया गया जब विभाग को एक प्रामाणिक विश्वास था कि जिन चिंताओं में याचिकाकर्ता संलग्न है, वे सही आय नहीं दिखा रहे थे और यह कि केवल तलाशी और जब्ती ही है जो गैर-जमानती परिसंपत्तियों का पता लगा सकती है।

(10) एच. एल. सिबाव के मामले (ऊपर दिए गए) के तथ्यों से पता चलता है कि यह मामला पटियाला के वकीलों के खिलाफ कार्रवाई के मामले में 1 अक्टूबर, 1974 को दिए गए एक नोट पर कैसे शुरू किया गया था। आय-कर आयुक्त द्वारा अन्य अधिकारियों के साथ चर्चा करने पर यह पता चला कि पटियाला के वकीलों द्वारा बड़े पैमाने पर चोरी की जा रही थी, उनमें से अधिकांश अनुमानित आय जमा कर रहे थे और सकल प्राप्तियों का समर्थन करने के लिए कोई सहायता या शुल्क-पुस्तक या संक्षिप्त विवरण नहीं रखा गया था। उक्त वकील एक अच्छी शैली में रह रहे थे और उनके पास ऐसी संपत्ति थी जिसका विभाग को खुलासा नहीं किया गया था और दोनों के अनुसार उनके द्वारा तब तक खुलासा नहीं किया जाना था जब तक कि उनके खिलाफ खंड 132 के तहत कार्रवाई नहीं की गई थी। ए. डी. आई. को चंडीगढ़, लुधियाना, अंबिला और रोहतक रेंज में अन्य लोगों के साथ इन मामलों को संसाधित करने के लिए कहा गया था, जहां इस मामले पर पहले ही आई. डी. 1 के साथ चर्चा की जा चुकी थी और वे केवल ऊपर बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे थे। ए. डी. आई. को विभिन्न श्रेणियों के लिए पेशेवर व्यक्तियों के लिए अलग-अलग फ़ोल्डर तैयार करने के लिए कहा गया था, जहां निर्देशों के साथ प्राधिकरण रखा जा सकता है, इस प्रकार, पटियाला धारकों के खिलाफ कुछ कार्रवाई की गई थी, क्योंकि आयुक्त को पता चला था कि बड़े पैमाने पर कर! उनके द्वारा चोरी का अभ्यास किया जा रहा था। उपरोक्त निष्कर्ष किसी भी बाहरी स्रोत से नहीं लिया गया था और इस तथ्य के सामने अनुमान लगाया गया था कि उनमें से अधिकांश सकल प्राप्तियों का समर्थन करने के लिए कोई लेखा या शुल्क-पुस्तिका या संक्षिप्त विवरण के बिना अनुमानित आय जमा कर रहे थे। जैसा कि उपरोक्त मामले में अदालत की खण्ड पीठ सही कहा है, आयकर आयुक्त द्वारा दर्ज किया गया नोट एक नीति की घोषणा की प्रकृति का था जिसका उद्देश्य चंडीगढ़, लुधियाना, अंबाला और रोहतक रेंज में रहने वाले लोगों को शामिल करना था। आत्यन्तिक रूप कोई जानकारी नहीं थी, कोई सबूत नहीं था, और कार्रवाई को सही ढंग से खारिज कर दिया गया था।

(11) जगमोहन महाजन बनाम आयकर आयुक्त (उपरोक्त) के मामले का निर्णय भी एच. एल. सिबबल के मामले (उपर्युक्त) में दिए गए निर्णय के आधार पर किया गया था। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि जगमोहन महाजन और अन्य लोगों के खिलाफ छापेमारी, और मेरे खिलाफ भी एच. आई. सिबबल का संचालन एक साथ किया गया था और वही जानकारी उपलब्ध थी जो श्री एच. एल. सिबबल के मामले में थी। एफ. ए. टी. में, प्राधिकरण के व्यापक वारंट जारी किए गए थे जिसमें उन मामलों में याचिकाकर्ताओं के नाम उस समय भरे गए थे जब इस न्यायालय में वकालत करने वाले एक अधिवक्ता श्री मुल्क राज मिहाजन के घर में तलाशी ली जा रही थी। उपरोक्त मामले में याचिकाकर्ता श्री मुल्क राज महाजन के साथ रह रहे थे। मनमोहन कृष्ण महाजन के मामले (ऊपर) के पहलू भी वही थे जो एच. एल. सिबबल और जगमोहन मिहाजन (ऊपर) के मामलों में उपलब्ध थे। वास्तव में, श्री मनमोहन कृष्ण महाजन भी इस न्यायालय में वकालत करने वाले एक अधिवक्ता थे, और उसी तरह की जानकारी जो एच. एल. सिबबल के मामले में उपलब्ध थी। ओम प्रकाश जिंदल (एस. आई. पी. आर. ए.) के मामले में केवल इतना ही माना गया है कि अधिनियम की खंड 132 की योजना में कहा गया है कि दो अधिकारियों द्वारा दो अलग-अलग चरणों में दिमाग को लागू किया जाना

है। अर्थात्, सबसे पहले, निरीक्षण निदेशक या आयुक्त द्वारा तलाशी का वारंट जारी करते समय यह पता लगाने के लिए कि किसी व्यक्ति के पास कोई आभूषण, आभूषण या धन आदि है, जिसे अघोषित संपत्ति माना जाता है, और दूसरा, अधिकृत अधिकारी द्वारा, जब तलाशी के दौरान कोई विशेष आभूषण, आभूषण या धन पाया जाता है, यह देखने के लिए कि उसे अघोषित संपत्ति के रूप में उचित रूप से माना जा सकता है। जहाँ तक तलाशी वारंट जारी करने से पहले या उसके समय मन लगाने के प्रश्न का संबंध है, हमारे पास यह अभिनिर्धारित करने में कोई हस्तक्षेप नहीं है कि विभाग के समक्ष पर्याप्त सामग्री थी और यह एक ऐसा मामला था जिसमें संबंधित अधिकारियों ने अपना मन लगाया था। जहाँ तक तलाशी वारंट जारी करने के बाद या ऐसी कार्यवाहियों के चलन के दौरान मन के प्रयोग का संबंध है, कोई तर्क नहीं है। याचिकाकर्ता की ओर से श्री बी. एस. गुप्ता ने कहा कि जो कुछ भी उठाया गया था, यह कहने के लिए कि संबंधित अधिकारियों ने यह नहीं देखा था कि आभूषण, गहने या पैसे पाए गए थे। दूसरी ओर, लिखित बयान में यह बताया गया है कि तलाशी और जब्ती के समय पाया गया स्टैक प्रस्तुत और दिखाए गए लेखा पुस्तकों में एस. के. सी. के. से मेल नहीं खाता था। किताबों में उल्लिखित सोने के गहने और यहाँ तक कि 16 जुलाई, 1987 को दर्ज सुम प्रकाश के बयान के अनुसार, यह दर्शाता है कि वे 4,88,297 रुपये के मूल्य के पहने गए थे, जबकि खोज के समय पाई गई मात्रा का मूल्य रु 16 लाख था। चांदी के आभूषणों, हीरे के आभूषणों आदि के संबंध में ऐसा ही है।

(12) बलवंत सिंह के मामले (ऊपर दिए गए) में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जिन आधारों पर विश्वास स्थापित किया गया है, वे अस्तित्वहीन हैं या अपरिवर्तनीय हैं या ऐसे हैं जिन पर कोई भी उचित व्यक्ति विश्वास नहीं कर सकता है, शक्ति का प्रयोग बुरा होगा; लेकिन इसके अलावा, अदालत निरीक्षण के निदेशक द्वारा किए गए प्रामाणिक विश्वास में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, और यह अदालत के लिए जांच करने के लिए खुला है कि क्या विश्वास के कारणों का कोई तर्कसंगत संबंध है या विश्वास के निर्माण के लिए प्रासंगिक संबंध है। कानून के इस प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं हो सकता है और न ही प्रतिवादी के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा ऐसा कोई विवाद उठाया गया है, लेकिन जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, ऐसे पर्याप्त आधार थे जिन पर 1961 के अधिनियम की खंड 132 के तहत राहत की आवश्यकता थी। पूरन मल (उपरोक्त) के मामले पर पहले ही चर्चा की जा चुकी है और हमारा विचार है कि उपरोक्त निर्णय याचिकाकर्ता के पक्ष में जाने के बजाय इसके खिलाफ हो जाता है। सेठ ब्रदर्स के मामले (ऊपर) में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि चूंकि 1961 के अधिनियम की खंड 132 के तहत शक्ति का प्रयोग, कर-प्रार्थना करने वाले के अधिकारों, गोपनीयता और स्वतंत्रता पर एक गंभीर आक्रमण किया जाता है, इसलिए शक्ति का उपयोग कानून के अनुसार और केवल उन उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए जिनके लिए कानून इसका प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है। यदि शक्ति के प्रयोग की शर्तें पूरी नहीं होती हैं तो कार्यवाही रद्द की जा सकती है। लेकिन हमारे सुविचारित विचार में, वर्तमान मामले में अपेक्षित शक्ति का उपयोग ईमानदारी से और आयकर अधिकारियों के वैधानिक कर्तव्यों को आगे बढ़ाने के लिए किया गया था। उक्त निर्णय वास्तव में याचिकाकर्ता के पक्ष में नहीं जाता है, बल्कि इसके खिलाफ हो जाता है। याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए दूसरे प्रश्न पर, और जिस पर हम वर्तमान में चर्चा करेंगे, उपरोक्त निर्णय भी याचिकाकर्ता के खिलाफ हो जाता है।

(13) याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री बी. एस. गुप्ता द्वारा उठाया गया दूसरा तर्क यह है कि याचिकाकर्ता-फर्म, जिसे मेसर्स जय भगवान ओम प्रकाश के नाम से जाना जाता है, के खिलाफ कोई प्राधिकरण नहीं था, और वास्तव में,

मेसर्स ओम प्रकाश सोम प्रकाश के खिलाफ, जिस परिसर में मेसर्स जय भगवान ओम प्रकाश का व्यवसाय चल रहा था, वहां तलाशी और जब्ती की कार्यवाही करने में प्रतिवादी-प्राधिकरणों की कार्यवाही पूरी तरह से अवैध और अधिकार क्षेत्र के बिना थी। पहली बार में, विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया तर्क बहुत आकर्षक प्रतीत होता है, लेकिन गहराई से जांच करने पर, हम उसमें कोई सार नहीं पाते हैं। यह सच है कि मेसर्स जय भगवान ओम प्रकाश एक साझेदारी वाली संस्था है, जिसमें ओम प्रकाश, सोम प्रकाश, अविनाश चंदर और विनय कुमार जैसे भागीदार शामिल हैं, और यह फर्म आयकर अधिनियम की खंड 185 के तहत विधिवत

पंजीकृत थी, जबकि मेसर्स ओम प्रकाश सोम प्रकाश एक एचयूएफ है और कोई भी व्यवसाय नहीं करता है, सिवाय इसके कि इसका मूल्यांकन एचयूएफ की स्थिति में धन कर अधिनियम के तहत किया जाता है। यह भी सच है कि प्राधिकरण का आदेश मैसर्स ओम प्रकाश सोम प्रकाश, सराफा बाजार, करनाल के नाम पर है। लेकिन केवल इस मामले के स्पष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए प्राधिकरण के वारंट को अमान्य नहीं किया जाएगा। मेसर्स जय भगवान ओम प्रकाश या मेसर्स ओम प्रकाश सोम, प्रकाश द्वारा संचालित सभी व्यावसायिक परिसरों के संबंध में विभाग द्वारा उपलब्ध जानकारी व्यावहारिक रूप से अधिकांश भागीदारों से संबंधित थी। इस प्रकार, यह देखा जाना चाहिए कि क्या ऐसी परिस्थितियों में मैसर्स ओम प्रकाश सोम प्रकाश, सराफा बाजार, करनाल के नाम से जारी प्राधिकरण का वारंट, जिसमें अकेले बाजार स्थापित है, मैसर्स जय भगवान ओम प्रकाश का व्यावसायिक परिसर अवैध होगा। बहिष्कार का आदेश सभी व्यक्तियों के परिसरों की तलाशी लेने के लिए था जैसा कि ऊपर विस्तृत किया गया है, यह देखते हुए कि ऐसी कार्यवाही के संबंध में फाइल कैसे शुरू हुई, प्राधिकरण के पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि ऐसे सभी व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है और उनके परिसरों की तलाशी ली जा सकती है। ओम प्रकाश, सो एन प्रकाश, भगत राम उपनाम भगत, परवीन कुमार, ज्ञान चंद और मदन लाई के नाम उनके निवास के टुकड़ों के साथ व्यक्तिगत रूप से उल्लिखित हैं। इसके बाद मैसर्स ओम प्रकाश सोम प्रकाश, सराफा बाजार, करनाल; मैसर्स ओम प्रकाश एंड संस, सराफा बाजार, करनाल; श्री भगत राम उपनाम भगत, सराफा बाजार, कमल के व्यावसायिक परिसर और ओल परवीन कुमार, सराफा बाजार, कमल के व्यावसायिक परिसर का उल्लेख आता है। सराफा बाजार में मेसर्स जय भगवान ओम प्रकाश जहां सराफा का व्यवसाय कर रहे हैं, वहां प्रदर्शित बोर्ड में मेसर्स ओम प्रकाश सोम प्रकाश का उल्लेख है और इस मामले के अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि मेसर्स ओम प्रकाश सोम प्रकाश द्वारा संचालित व्यवसाय को जय भगवान ओम प्रकाश के रूप में शैलीबद्ध किया गया है। इतना ही नहीं, सोम प्रकाश ने इस तरह की कार्यवाही के समय उपरोक्त तथ्य को स्वीकार किया।

मेसर्स ओम प्रकाश सोम प्रकाश पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरण द्वारा रुपये 3,500, जिसे निर्धारण वर्ष 1984-85 के लिए मेसर्स जय भगवान ओम प्रकाश के लाभ और हानि खाते में डेबिट किया गया था। इसके अलावा, एक लाख रुपये का रिफंड। स्वर्ण नियंत्रण प्रशासन द्वारा अनुमत उपरोक्त जुर्माने में से रुपये 3,250 को फिर से मेसर्स जय भगवान ओम प्रकाश के लाभ और हानि खाते में जमा किया गया। मेसर्स जय भगवान ओम प्रकाश के सहयोगी क्यू. एम. प्रकाश ने आयकर अधिकारी को संबोधित 6 जून, 1937 के पत्र के माध्यम से स्वयं अनुरोध किया कि उन्हें 5 लाख रुपये की राशि वापस की जाए। मेसर्स जय भगवान ओम प्रकाश के लाभ और हानि खाते में रुपये 3,250 जमा किए जाएं। इस प्रकार, यह स्पष्ट रूप से स्थापित है कि तलाशी परिसर मेसर्स ओम प्रकाश सोम प्रकाश द्वारा मेसर्स जय भगवान सोम प्रकाश के नाम और शैली में व्यवसाय के संबंध में चलाया जा रहा था। तलाशी के समय अधिकारियों द्वारा दर्ज सोम प्रकाश का बयान मामले को किसी भी विवाद के दायरे से परे रखता है जब वह मैसर्स जय भगवान ओम प्रकाश, सराफा बाजार, कमल के रूप में श्री ओम प्रकाश के साथ एक भागीदार के रूप में, जो उनका असली भाई है और समान भागीदार है, स्वीकार करता है कि फर्म सराफा व्यवसाय में काम कर रही थी। कथन का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:—

“उन्होंने कहा कि मैं मैसर्स जय भगवान दास सोम प्रकाश, सराफा बाजार, कमल के रूप में शैलीबद्ध फर्म में भागीदार हूँ, जिसमें मेरे असली भाई श्री ओम प्रकाश समान भागीदार हैं। यह फर्म सराफा व्यवसाय में काम करती है। हम कमल में बी-वार्ड, कमल, पी. ए. नं. एफ. आई. 9173 में आयकर के लिए मूल्यांकन किए जाते हैं। सोम प्रकाश ओम प्रकाश द्वारा संचालित व्यवसाय को मेसर्स जय भगवान दास सोम प्रकाश, कमल के रूप में शैलीबद्ध किया गया है।”

(14) विभाग द्वारा यह बयान अनुलग्नक (1) के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त बयान पर सोम प्रकाश के हस्ताक्षर बहस के दौरान स्वीकार किए गए हैं। कुछ अतिव्यापी और भ्रम है, लेकिन यह स्पष्ट है कि सोम प्रकाश मेसर्स जय भगवान ओम प्रकाश फर्म में भागीदार थे। तलाशी के समय उनसे पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि वह अपने साथी से परामर्श करने के बाद इस सवाल का जवाब देंगे। उनसे एक और सवाल पूछा गया कि उन्होंने पहले कहा था कि फर्म में केवल दो भागीदार थे, लेकिन इस फर्म में चार भागीदार हैं। इस विशिष्ट प्रश्न पर उन्होंने कहा कि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। इसके अलावा, अगर सोम प्रकाश मेसर्स जय भगवान ओम प्रकाश के भागीदार नहीं थे, तो यह उम्मीद की जा रही थी

कि जब तलाशी अभियान चल रहा था, तब उन्होंने इस संबंध में कुछ आपत्तियां उठाई होंगी और स्वीकार किया कि वे दुकान में मौजूद थे

इसके अलावा उनके लिए 4 लाख रुपये की राशि की पेशकश करने का कोई सवाल ही नहीं था, जिसका प्रस्ताव संशोधित कर बाद में 6 लाख रु कर दिया, अगर वे मैसर्स जय भगवान ओम प्रकाश फर्म के भागीदार नहीं थे। संपत्ति अर्जित करने की अवधि के बारे में उनसे पूछे गए अन्य प्रश्नों के संबंध में, उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने मार्च 1987 के बाद ऐसी संपत्ति अर्जित की थी। इसके अलावा, महादेव बॉम्बेवाला के बयान से यह भी पता चलता है कि उक्त व्यक्ति मैसर्स ओम प्रकाश सोम प्रकाश की ओर से चांदी पिघल रहे थे। मामला यहीं नहीं रुकता है और यह 2 मार्च, 1977 को अधीक्षक (रोकथाम) श्री जी. डी. थापर के समक्ष ओम प्रकाश के पुत्र श्री कैलाश चंद के बयान से सामने आता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी फर्म का नाम मैसर्स ओम प्रकाश सोम प्रकाश है, जो पिछले 30 से 35 वर्षों से चल रहा है। उपरोक्त सामग्री पर, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क केवल यह है कि प्राधिकरण के वारंट जारी करने से पहले कोई सामग्री नहीं थी, न ही कोई दिमाग का उपयोग किया गया था कि मैसर्स जय भगवान ओम प्रकाश, एक साझेदारी संस्था, जिसका परिसर सराफा बाजार, करनाल में स्थित था, मैसर्स जय भगवान ओम प्रकाश के नाम पर चुपके से या गुप्त रूप से व्यवसाय कर रहा था, लेकिन वास्तव में व्यवसाय मैसर्स ओम प्रकाश सोम प्रकाश का था। सेठ ब्रदर्स (उपरोक्त) के मामले के तथ्यों से पता चलता है कि सेठ ब्रदर्स के नाम पर एक प्राधिकरण था, जबकि फर्म के भागीदारों या निर्धारिती द्वारा किए गए अन्य व्यवसाय के संबंध में लेखा पुस्तकों और अन्य दस्तावेजों की भी तलाशी ली गई और उन्हें जब्त कर लिया गया। मामले पर विचार करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह सुझाव कि लेखा पुस्तकें और अन्य दस्तावेज, जिन्हें कब्जा में लिया जा सकता है, केवल वही होने चाहिए जो मैसर्स सेठ ब्रदर्स के नाम पर किए गए व्यवसाय से सीधे संबंधित हों, इसमें कोई सार नहीं है। निर्धारिती के फर्म के भागीदारों द्वारा किए गए अन्य व्यवसायों के संबंध में लेखा पुस्तकें और अन्य दस्तावेज निश्चित रूप से प्रासंगिक होंगे क्योंकि वे लेनदेन और आपूर्ति सामग्री के बीच अंतर संबंध को दर्शाते हैं जो फर्म द्वारा आयकर की चोरी के मामले में असर डालते हैं। तथ्य यह है कि अधिकारियों ने तलाशी ली थी और अन्य फर्मों और कंपनियों के नाम पर किए गए व्यवसाय के संबंध में लेखा पुस्तकों और दस्तावेजों को जब्त कर लिया था, तलाशी और जब्ती को अवैध नहीं माना गया था। प्राधिकरण का वारंट निश्चित रूप से ओम प्रकाश को संदर्भित करता है, जिसे जय भगवान ओम प्रकाश फर्म में एक भागीदार भर्ती किया जाता है, उस स्थान को भी संदर्भित करता है जहाँ सराफास का व्यवसाय किया जा रहा है। मान लीजिए, ओम प्रकाश सोम प्रकाश फर्म न तो सराफा बाजार, करनाल में कोई व्यवसाय कर रही है और न ही उस शहर में किसी अन्य स्थान पर। वर्तमान मामले के अभिलेखों पर यह साबित हो गया है कि

भले ही सराफा बाजार, कमल में, यह फर्म मैसर्स जय भगवान ओम प्रकाश है, जो व्यवसाय या कागज चला रही है, लेकिन आयकर आदि के उद्देश्यों के लिए वास्तविक व्यवसाय ओम प्रकाश सोनी प्रकाश का है। केवल यह तथ्य कि प्राधिकरण का वारंट जारी करने से पहले यह कहीं भी विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया था कि वास्तव में, सराफा बाजार, कमल में किया जाने वाला व्यवसाय मैसर्स ओम प्रकाश सोम प्रकाश से संबंधित है। और केवल राजस्व से बचने और अधिकारियों को धोखा देने के उद्देश्य से, जय भगवान ओम प्रकाश का नाम बनाया गया है, इस मामले के विचित्र तथ्यों और परिस्थितियों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेनामी या काला धन, जैसा कि इसे कहा जा सकता है, इस देश की अर्थव्यवस्था को तेजी से खा रहा है। बेईमान व्यक्तियों को आर्थिक जीवन को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, और जैसा कि पून मल के मामले (ऊपर) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संक्षिप्त रूप से कहा गया है कि यह हमारे आर्थिक जीवन का एक सर्वविदित तथ्य है कि बड़ी मात्रा में बेनामी धन परिसंचरण में है जो इसके ताने-बाने को खतरे में डाल रहा है और एक ऐसे देश में जिसने कराधान की उच्च दरों को अपनाया है, बेनामी धन का एक बड़ा हिस्सा आम तौर पर सरकारी खजाने में भरना चाहिए। ऐसा करने के बजाय यह अर्थव्यवस्था को विकृत करता है। इसलिए, समुदाय के हित में यह सही है कि वित्तीय प्राधिकरणों के पास कर चोरी को रोकने के लिए पर्याप्त शक्तियां होनी चाहिए।

(15) श्री गुप्ता का यह तर्क कि विभाग के पास जो जानकारी उपलब्ध थी, साथ ही वह सामग्री और कारण जिसके आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, याचिकाकर्ता को उपलब्ध कराया जाना चाहिए था और लिखित बयान में उस प्रभाव के लिए अभिवचनों की कमी कार्रवाई को दूषित करेगी, हमें प्रभावित नहीं करती है। पूरी याचिका में उपरोक्त आधारों पर विवादित कार्रवाई को कोई चुनौती नहीं दी गई है। एक बार जब उपरोक्त आधारों पर अभिवचनों का पूरी तरह से अभाव हो जाता है, तो हम प्रतिवादी प्राधिकरणों की ओर से सामग्री की आपूर्ति करने और उन कारणों के लिए कोई दायित्व नहीं पाते हैं जिनके आधार पर आयकर आयुक्त द्वारा तलाशी के प्राधिकरण का आदेश जारी किया गया था। दलीलों के दौरान याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक रूप से प्रस्तुत किए जाने पर, विभाग को उन तथ्यों को हमारे ध्यान में लाने में संकोच नहीं हुआ जो अधिकारियों द्वारा दिमाग का उपयोग करते हैं। हालाँकि, श्री गुप्ता ने अपने उपरोक्त तर्क के लिए आयकर अधिकारी, आई-वार्ड हुंडी सर्कल, कलकत्ता बनाम मदनानी इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड (118 आई. टी. आर.1)

में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के साथ-साथ दिए गए, उच्च न्यायालय द्वारा बीजू पटनायक बनाम आयकर केंद्रीय मंडल, कटक (102 आई. टी. आर. 96) और दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ के निर्णय द्वारा एल. आर. गुप्ता बनाम भारत संघ (1991 खण्ड. 59 टैक्समैन 305) निर्णय पर भी भरोसा किया है।

मदनानी इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड मामले (उपरोक्त) के तथ्यों से पता चलेगा कि मूल्यांकन वर्ष के लिए उक्त मामले के प्रतिवादी के मूल मूल्यांकन में उसके द्वारा उन लेनदारों को दिए गए कुछ ब्याज, जिनसे उसने हुंडी उधार लेने का दावा किया था, को कटौती योग्य व्यय के रूप में अनुमति दी गई थी। बाद में, चार साल के अंतराल के बाद, इस आधार पर प्रतिवादी के मूल्यांकन को फिर से खोलने के लिए एक नोटिस जारी किया गया कि हुंडी द्वारा प्रस्तुत ऋण का लेनदेन फर्जी था और प्रतिवादी द्वारा किसी भी लेनदार को कोई ब्याज नहीं दिया गया था और इसे गलत तरीके से अनुमति दी गई थी। उपरोक्त नोटिस की वैधता को उच्च न्यायालय में रिट याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई थी। आयकर कार्यालय ने जवाबी शपथ पत्र में इस आधार पर तथ्यों का खुलासा करने से इनकार कर दिया कि यदि इस तरह के तथ्यों का खुलासा किया जाता है, तो यह राजस्व के हितों के प्रति गंभीर पूर्वाग्रह पैदा करेगा और मूल्यांकन को फिर से खोलने के उद्देश्य को विफल कर देगा। हालाँकि, इसके बाद उन्होंने एक और शपथ पत्र दायर किया जिसमें कहा गया कि मूल्यांकन वर्ष के लिए प्रतिवादी के मूल्यांकन के दौरान यह पता चला कि मूल्यांकन वर्ष के लिए प्रतिवादी की लेखा पुस्तकों में हुंडियों की प्रतिभूति के खिलाफ ऋण के रूप में दिखाई गई विभिन्न वस्तुएं वास्तव में काल्पनिक थीं और कुछ व्यक्तियों के नाम के खिलाफ क्रेडिट वास्तविक नहीं पाए गए थे और उस परिसर में आयकर अधिकारी को यह दिखाई दिया कि प्रतिवादी मूल्यांकन के लिए आवश्यक सभी भौतिक तथ्यों को पूरी तरह से और सही मायने में प्रकट करने में विफल रहा था और इस तरह की विफलता के कारणों से, उसकी आय का एक हिस्सा मूल्यांकन से बच गया था। उपरोक्त तथ्यों पर उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि आयकर अधिकारी द्वारा अपने पहले शपथ पत्र में लिया गया रुख स्पष्ट रूप से असमर्थनीय था क्योंकि आईटीओ की ओर से विश्वास करने के कारणों का अस्तित्व एक न्यायोचित मुद्दा था और यह अदालत को संतुष्ट करना था कि क्या वास्तव में, आईटीओ के पास यह मानने के कारण थे कि आय पूर्ण और सही खुलासा करने में प्रतिवादी की विफलता के कारण मूल्यांकन से बच गई थी (जोर दिया गया)। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि जैसा कि आई. टी. ओ. ने दूसरे शपथ पत्र में केवल अपना विश्वास व्यक्त किया था, लेकिन ऐसी कोई सामग्री निर्धारित नहीं की थी जिसके आधार पर वह इस तरह के विश्वास पर पहुंचा था, ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके आधार पर अदालत को संतुष्ट किया जा सके कि उसके पास यह विश्वास करने का कारण था कि प्रतिवादी की आय का एक हिस्सा भौतिक तथ्यों का सही और पूर्ण खुलासा करने में विफल रहने के कारण मूल्यांकन से बच गया था।

उपरोक्त रिपोर्टों से दिए गए तथ्यों के विवरण से कि रिट याचिका में यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि आयकर अधिकारी के पास यह मानने का कोई कारण नहीं था कि प्रतिवादी की आय का कोई भी हिस्सा भौतिक तथ्यों का सही और पूर्ण प्रकटीकरण करने में विफल रहने के कारण मूल्यांकन से बच गया था। जैसा

कि ऊपर उल्लेख किया गया है, वर्तमान मामले में, रिट याचिका में कहीं भी ऐसी कोई चुनौती नहीं दी गई है। हालाँकि, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, प्रतिवादी ने इस अदालत और अदालत के समक्ष पूरी सामग्री रखी है, पूरे रिकॉर्ड को देखने के बाद, प्राधिकरण के वारंट जारी करने में, संतुष्ट हैं कि अधिकारियों के सामने पर्याप्त जानकारी थी, शिकायतकर्ता द्वारा बनाए गए तथ्यों को सत्यापित किया गया था और याचिकाकर्ता के खिलाफ अंततः कार्रवाई करने से पहले बहुत सारी चर्चा और गुप्त पूछताछ की गई थी।

(16) मामले के तथ्यों से यह भी पता चलेगा कि निर्धारिती का मामला यह था कि ऐसी कोई सामग्री नहीं थी और न ही हो सकती थी जिससे आयकर अधिकारी की ओर से इस विश्वास की जानकारी मिल सके कि संबंधित निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती की आय मूल्यांकन से बच गई थी क्योंकि वह अपनी ओर से उन सभी भौतिक तथ्यों का पूरी तरह से और सही मायने में खुलासा करने में विफल रहा था जो उसके मूल्यांकन के लिए आवश्यक थे। उक्त मामले के याचिकाकर्ता से पूछताछ करने पर अदालत ने कहा कि विश्वास के अस्तित्व को निर्धारिती द्वारा चुनौती दी जा सकती है, हालाँकि उक्त विश्वास के कारणों की पर्याप्तता को इतना चुनौती नहीं दी जा सकती है और आयकर अधिकारी का स्पष्ट कर्तव्य था कि वह रिट याचिका के विरोध में अपने हलफनामे में उन कारणों को ठीक से निर्धारित करे जिनके कारण उसकी ओर से विश्वास का निर्माण हुआ और शपथ पत्र दायर करने का उद्देश्य अदालत को सभी आवश्यक और प्रासंगिक सामग्री और तथ्यों से अवगत कराना है और यह कि ऐसी सामग्री और तथ्यों को शपथ और पुष्टि पर अनिवार्य रूप से कहा जाना चाहिए। यह सच है कि अभिलेख की मांग करने और उसे देखने की अदालत की शक्ति आयकर अधिकारी को हलफनामे में सभी प्रासंगिक और भौतिक तथ्यों को रखने की अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करती है, लेकिन ऐसा करने से पहले, याचिका में ही इस तरह का शपथ पत्र आमंत्रित करने के लिए एक आवश्यक नींव रखी जानी चाहिए। एक बार जब विभाग पूरी सामग्री के रूप में स्पष्ट रूप से दिखा देता है, तो निश्चित रूप से, केवल एक सूचना देने वाले का नाम छिपाने के लिए, हमें कोई कारण नहीं मिलता है कि उसने सामग्री का खुलासा नहीं किया है और जिन कारणों पर कार्रवाई की गई थी, यदि उस दिशा में अभिवचन रिट याचिका में ही किए गए थे। उसी तर्क की समानता पर, हम याचिकाकर्ता के लिए यू. आर. गुप्ता बनाम भारत संघ (उपरोक्त) के फैसले से कोई सांत्वना नहीं पाते हैं।

(17) श्री गुप्ता ने एन. के. टेक्सटाइल मिल्स बनाम आयकर आयुक्त, नई दिल्ली (एल. एक्स. II. टी. आर. 58), और डॉ. नंद लाल बनाम आयकर आयुक्त (170 आईटीआर 592), और गंगा सरन एंड संस प्राइवेट लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, नई दिल्ली (130 आई. टी. आर. 1 (एस. सी.)) पर भी भरोसा किया है। इन प्राधिकारियों के आधार पर यह स्पष्ट करने की कोशिश की जाती है कि आयकर अधिनियम की खंड 132 में "विश्वास करने का कारण है" शब्द उस विश्वास के लिए विश्वास और कारणों के अस्तित्व को अभिनिर्धारित करते हैं और यह कि विश्वास सद्भावना से रखा जाना चाहिए। इस फैसले के पहले भाग में गिने गए विस्तृत तथ्यों पर हम पाते हैं कि ऐसी सूची सामग्री थी जिसके आधार पर उस विश्वास के लिए विश्वास और कारणों का अस्तित्व बनाया जा सकता था और यह भी कि यह प्रामाणिक विश्वास था। इस प्रकार, उपरोक्त तीन निर्णय भी याचिकाकर्ता को कोई सहायता प्रदान नहीं करते हैं।"

(18) निर्णय के पहले भाग में नियम 1962 के नियम 112 के प्रासंगिक प्रावधानों को उद्धृत किया गया है। मान लीजिए कि प्राधिकरण का वारंट आयकर आयुक्त द्वारा जारी किया गया था जिसे तलाशी वारंट जारी करने का अधिकार था। प्राधिकरण लिखित रूप में और प्राधिकरण जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर के तहत था। नियम 112 के उप नियम 4-बी में निहित प्रावधानों के तहत अधिकृत अधिकारी किसी भी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता कर सकता है जो इमारत, स्थान, पोत, वाहन या एयरक्राफ्ट में स्थित किसी भी बॉक्स, लॉकर, सेफ, अलमिरा या किसी अन्य पात्र का मालिक था, या जिसका तत्काल कब्जा या नियंत्रण था। इसे खोलने और इसकी सामग्री की जांच करने के लिए निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए। इस प्रकार उपरोक्त उपनियम से यह कहा गया है कि अधिकृत अधिकारी को किसी भी व्यक्ति से, जो मालिक हो सकता है या जिसका तत्काल कब्जा हो सकता है, संबंधित अधिकारी को, भवन या इमारत में जगह उपलब्ध कराने के लिए कहने की शक्ति थी ताकि प्राधिकरण के वारंट के अनुसरण में तलाशी ली जा सके। तलाशी लेने से पहले, उस इलाके के सम्मानित निवासी जिसमें इमारत स्थित थी। दो गवाह उपलब्ध थे जिन्होंने पंचनामा देखा था। उपरोक्त गवाहों की उपस्थिति में तलाशी ली गई और तलाशी के दौरान जब्त की गई सभी चीजों की सूची तैयार की गई और इसकी प्रति मेसर्स जय भगवान ओम प्रकाश के भागीदारों में से एक सोम प्रकाश को दी गई।

इस प्रकार प्रक्रिया का सावधानीपूर्वक पालन किया गया। याचिकाकर्ता का विद्वान अधिवक्ता कुछ भी इंगित नहीं कर सका जिसने 1962 के नियमों के नियम 112 के तहत प्रदान किए गए किसी भी प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का उल्लंघन किया हो।

(19) पहले निर्दिष्ट किए गए निर्णयों पर भरोसा करने के अलावा, विभाग की ओर से पेश श्री साहनी नारायण आर. बांदेकर बनाम द्वितीय आयकर अधिकारी (177 आई. टी. आर 207) पर भी भरोसा करते हैं। इस मामले के तथ्यों से पता चलता है कि 'बी' और उनकी पत्नी ने कई प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां शुरू की थीं जो जम्मू और कश्मीर राज्य में पंजीकृत थीं, हालांकि पूरा व्यवसाय इन कंपनियों द्वारा गोवा में किया जाता था जहां 'बी' और उनकी पत्नी रहती थीं। आयकर अधिकारियों ने 'बी' और उनकी पत्नी के आवासीय और व्यावसायिक परिसरों की तलाशी ली। तलाशी के दौरान, 'बी' और उसकी पत्नी द्वारा रखी गई प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के नाम पर और कुछ अन्य व्यक्तियों के नाम पर रुपये की राशि के लिए सावधि जमा रसीदें, 30 लाख रुपये नकद और 12 लाख 6 हजार रुपये मूल्य के आभूषण बरामद किए गए। आयकर अधिकारी ने आयकर नियम, 1962 के नियम 112ए के तहत 'बी' और उनकी पत्नी को कारणदर्शक नोटिस जारी किया और उन्हें सुनने के बाद आयकर अधिनियम की खंड 132 (5) के तहत एक आदेश पारित किया, जिसमें कहा गया कि आकलन वर्षों के लिए कर और जुर्माना जब्त की गई संपत्ति के मूल्य से अधिक था और इसलिए, जब्त की गई संपत्ति को उनके पास रखना आवश्यक था। निर्धारित द्वारा दायर रिट याचिका में, अन्य बातों के साथ-साथ यह भी तर्क दिया गया कि आयकर आयुक्त द्वारा जारी प्राधिकरण का वारंट अमान्य था क्योंकि आयुक्त के पास ऐसी कोई सामग्री या जानकारी नहीं थी जिससे वह यह विश्वास कर सके कि तलाशी का निर्देश देने के लिए पूर्व-आवश्यक शर्तें मौजूद थीं, और यह भी कि अधिनियम की खंड 132 (9ए) के प्रावधानों का इस आधार अन्य बातों के साथ साथ उल्लंघन किया गया था कि अधिकृत अधिकारी ने जब्त की गई संपत्तियों को आयकर अधिकारी को नहीं सौंपा था और इसलिए, अधिनियम की खंड 132 (5) के तहत पारित आदेश को कायम नहीं रखा जा सका। फाइल के अवलोकन पर यह अभिनिर्धारित किया गया कि आयुक्त द्वारा शक्ति का प्रयोग उचित था। आयुक्त ने तीन अनाम याचिकाओं के आधार पर निरीक्षण के सहायक निदेशक द्वारा प्रस्तुत नोट पर विचार किया था, इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले कि अधिनियम की खंड 132 (5) के तहत शक्ति का प्रयोग आवश्यक था, निरीक्षण के सहायक निदेशक के साथ सम्मेलन में आयोजित अनाम याचिकाओं पर विचार किया था। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि यह प्रतिग्रहण करना करना संभव नहीं है कि किसी भी मामले में गुमनाम याचिकाओं द्वारा से प्राप्त जानकारी के बल पर शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है और व्यापक जानकारी और की गई विस्तृत जांच पर विचार करने पर, यह निष्कर्ष अपरिहार्य था कि आयुक्त द्वारा बनाया गया विश्वास वास्तविक और प्रामाणिक था और इसलिए, खंड 132 (5) के तहत आयुक्त द्वारा शक्ति का प्रयोग दोषपूर्ण नहीं था और खोज त्रुटिपूर्ण थी। ऐसा करना अवैध नहीं था, जैसा कि ऊपर दिखाया गया है, मामला एक विस्तृत शिकायत और याचिकाकर्ता, विभिन्न भागीदारों और उन चिंताओं के खिलाफ लगाए गए अपने आरोपों के समर्थन में शिकायतकर्ता द्वारा व्यक्तिगत रूप से किए गए बयानों की प्राप्ति पर सामने आया जिसमें याचिकाकर्ता या उसके सहयोगी भागीदार थे। आयकर अधिकारी इससे संतुष्ट नहीं थे और वे व्यक्तिगत रूप से करनाल गए जहां मामले की आगे जांच की गई। अधिकारी द्वारा करनाल में विभिन्न स्थानों पर जाकर पूछताछ करने और साक्ष्य एकत्र करके विभिन्न व्यक्तियों से मिलने में पर्याप्त समय लगा। इस मामले पर समय-समय पर उच्च अधिकारियों के साथ चर्चा की जाती थी जो संबंधित अधिकारी से अधिक जानकारी एकत्र करने के लिए कह रहे थे। इस मामले में पूछताछ करने वाले अधिकारियों द्वारा प्रमाणित जानकारी पर ही आयकर आयुक्त इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि खंड 132 की पूर्व-आवश्यकताएं पर्याप्त रूप से बनाई गई थीं। वर्तमान मामले में कार्रवाई, हमारे विचार में, पूरी तरह से उचित थी और इसे किसी भी आधार पर गलत नहीं ठहराया जा सकता है। श्री गुप्ता का अंतिम निवेदन कि खंड 132 (5) के तहत जारी किए गए पहले नोटिस में एक अलग नाम/पते का उल्लेख किया गया है, जबकि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए रेप्टी पर तुरंत एक बदलाव किया गया था और खंड 132 (5) के तहत दूसरा नोटिस सही नाम के साथ दिया गया था, प्रतिवादी के वकील द्वारा एक अनजाने में हुई गलती के लिए समझाया गया है। 31 जुलाई 1987 को नियम 1962 के नियम 112-ए के तहत पहला नोटिस मैसर्स ओम प्रकाश सोम प्रकाश, जोरियन कुआं करनाल के नाम पर आयकर अधिकारी, ए-वार्ड, करनाल द्वारा जारी किया गया था। जब उपरोक्त सूचना के अनुसरण में, आयकर अधिकारियों के ध्यान में लाया गया कि मैसर्स ओम प्रकाश सोम प्रकाश फर्म जोरीन कुआं, करनाल में कोई व्यवसाय नहीं कर रही थी और न ही उसका कोई व्यवसाय था और अधिनियम की खंड 132 के तहत मैसर्स ओम पारका के किसी भी परिसर में कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। श्री

सोम प्रकाश, आयकर अधिकारी द्वारा अधिनियम के नियम 112 ए के तहत तुरंत एक नया नोटिस जारी किया गया था जिसमें जय भगवान ओम प्रकाश करनाल आदि के व्यवसाय के संबंध में सही नाम अर्थात मेसर्स ऑन प्रकाश सोम प्रकाश का उल्लेख किया गया था। प्राधिकरण की छूट स्वीकार्य रूप से ओम प्रकाश सोम प्रकाश, सराफा बाजार, करनाल, पंचनामा के नाम पर है और ओम प्रकाश सोम प्रकाश के नाम पर मौके पर तैयार की गई सूची है। मेसर्स जय भगवान ओम प्रकाश के व्यवसाय के संबंध में सराफा बाजार, करनाल किसी को भी संदेह में नहीं छोड़ेगा कि जोरियन कुआं में ओम प्रकाश सोम प्रकाश के नाम का उल्लेख पहली सूचना में लिपिकीय या टंकण संबंधी गलती थी। ऊपर पुनः प्रस्तुत किए गए विस्तृत तथ्यों और परिस्थितियों पर, हम प्रतिग्रहण करने के लिए इच्छुक हैं

(20) याचिकाकर्ता के वकील द्वारा और कुछ भी तर्क नहीं दिया गया है। इस प्रकार, इस याचिका में कोई बल नहीं मिलने पर हम इसे खारिज कर देते हैं। हालांकि, पार्टियों को अपना खर्च खुद वहन करने के लिए छोड़ दिया गया है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्या न्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आकाश जिंदल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

गुरुग्राम, हरियाणा